असर न्यूज़

Email: asarnewsinfo@gmail.com
RNI. NO. DELHIN/68203/98

Web: www.asarnews.com

दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष: 29 अंक: 28 सोमवार, 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 मूल्य: 2 रू. पृष्ठ:04

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एजीएम में कई अहम फैसले, चांदनी चौक, टाउन हॉल, जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन क्षेत्र के विकास पर जोर

पुरानी दिल्ली के पुनर्विकास को नई दिशा, 'इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम' का गठन

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की व्यापक योजना पर कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास मंत्री एवं निगम के उपाध्यक्ष आशीष सूद, प्रबंध निदेशक संदीप कुमार तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विरासत संरक्षण, आधारभूत ढांचे के विकास, पर्यटन संवर्धन और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार का विकास उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप किया जाए। उन्होंने प्रतिदिन आने वाले लाखों लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों, बेहतर नागरिक सुविधाओं और समुचित व्यवस्थाओं के विकास पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक टाउन हॉल के पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसका एक प्रमुख प्रवेश एवं निकास चांदनी चौक की ओर भी विकसित किया जाए, ताकि यह इमारत एक प्रमुख विरासत एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सके। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करने पर जोर दिया और कहा कि चांदनी चौक का विकास व्यापार, पर्यटन, खरीदारों और स्थानीय निवासियों के हितों के अनुरूप होना चाहिए। पर्यटकों की सुविधा के लिए चांदनी चौक में एक समर्पित कंट्रोल रूम स्थापित करने, व्यवस्थित पार्किंग विकसित करने तथा यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर एवं उसके पीछे के क्षेत्र के समग्र विकास का विस्तृत ब्लू प्रिंट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही जामा मस्जिद क्षेत्र और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास की कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि पुरानी दिल्ली का विकास केवल आधारभूत ढांचे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विरासत संरक्षण, पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों, नागरिक सुविधाओं और पर्यावरणीय संतुलन को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

इसके तहत ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण, आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। इसलिए विकास कार्य ऐसे हों, जिनसे पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और स्थापत्य सौंदर्य सुरक्षित रहे तथा स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों सभी को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। शहरी विकास मंत्री एवं निगम के उपाध्यक्ष आशीष सूद ने कहा कि चांदनी चौक और आसपास के ऐतिहासिक क्षेत्रों के पुनर्विकास में इतिहासकारों, विरासत संरक्षण विशेषज्ञों, स्थापत्य विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाएगा, ताकि मूल ऐतिहासिक स्वरूप और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि पुरानी दिल्ली लगभग 7.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है।

गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में शुरू किया वृक्षारोपण कार्यक्रम, 405 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में 'मिशन फाइव मिलियन ट्रीज' के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान, उन्होंने करीब 405 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अहमदाबाद महानगर निगम की ओर से 'मिशन फाइव मिलियन ट्री' के तहत विज्ञान भवन, साइंस सिटी, सोला में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंच पर उनका भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 101 ऑक्सीजन पार्क और हेरिटेज पार्क का ई-लोकार्पण किया। इसके अलावा अहमदाबाद नगर निगम, औडा और सड़क व भवन विभाग की लगभग 405 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का ई-लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट, राज्य सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक, नगर निगम के पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से विकसित 101 ऑक्सीजन पार्कों में लगभग 9 लाख 66 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में 22 लाख 71 हजार से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इनमें से 62 पार्क गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां लगभग 16 लाख पौधों का रोपण किया गया है। इन पार्कों से शहर में हरित क्षेत्र बढ़ेगा, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण और शहरी गर्मी कम होगी तथा नागरिकों को योग, वॉक और मनोरंजन के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होंगे।इन ऑक्सीजन पार्कों में 45 पार्कों में बच्चों के लिए प्ले एरिया और 19 पार्कों में खेलकूद की सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। साथ ही वर्षा जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज और जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी ये पार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।80 नई एयर-कंडीशंड इलेक्ट्रिक बीआरटीएस बसों का शुभारंभ किया गया। जेबीएम कंपनी की ओर से जीसीसी मॉडल के तहत संचालित इन बसों पर हर वर्ष लगभग 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

इन बसों के शुरू होने से यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक, वातानुकूलित और प्रदूषण मुक्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। फिलहाल अहमदाबाद बीआरटीएस के पास कुल 333 बसें हैं, जिनमें 200 इलेक्ट्रिक बसें पहले से संचालित हो रही हैं। अब पहले चरण में 80 नई इलेक्ट्रिक एसी बसें शामिल की जा रही हैं। भविष्य में पूरी बीआरटीएस सेवा को इलेक्ट्रिक फ्लीट में बदलने की योजना बनाई गई है। इसके लिए एएमटीएस और बीआरटीएस के लिए कुल 325 इलेक्ट्रिक एसी बसों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

ईरान के 140 ठिकानों पर अमेरिका का प्रहार, तेहरान का पलटवार, क्रूज मिसाइल मार गिराई, खाड़ी देशों में भीषण हमले

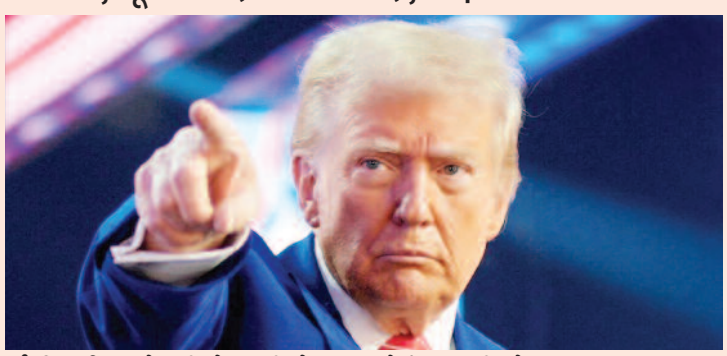

नई दिल्ली। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि रविवार के हमलों में उसने लगभग 140 ठिकानों को निशाना बनाया, जो पिछले दो दौर के हमलों की तुलना में कहीं ज्यादा है, इसके साथ ही मिसाइल व ड्रोन लॉन्च साइट, गोला-बारूद के भंडार, संचार उपकरण और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कमांड ने कहा कि इन हमलों से ईरान की नागरिक जहाजों को धमकाने की क्षमता कमजोर होगी। वहीं, अमेरिकी हमले के दौरान खोर्रमाबाद में IRGC एयरोस्पेस फोर्स के नए एयर डिफेंस सिस्टम ने एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी के कई देशों जिनमें बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान शामिल हैं, उनपर हमले किए। अब लड़ाई के इस नए दौर ने 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की कोशिशों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तेल और प्राकृतिक गैस के लिए एक अहम रास्ता होने के कारण होर्मुज बातचीत में मुख्य अड़चन बन गया है, और पिछले हफ्ते हुई बार-बार की लड़ाई ने बातचीत को टूटने के कगार पर पहुंचा दिया है।

इस बीच, कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों में एक और ईरानी सैनिक की मौत हो गई है। स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सशस्त्र सेना की नौसेना के लेफ्टिनेंट हामिदरेजा देहघानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जास्क बंदरगाह पर किए गए हमले में मारे गए। बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले सीजफायर के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने का ऐलान किया था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया के लिए सबसे खास दिन बताया था। इस फैसले के बाद उम्मीद जगी थी कि ईरान के इस कदम से दोनों देशों को शांति की दिशा में बड़ी कामयाबी मिल जाएगी।

संपादकीय

दिल्ली में गड्ढा या गड्ढे में दिल्ली?

"कहते हैं दिल्ली देश का दिल है, लेकिन आज यह दिल जगह-जगह गहरे जख्मों से भरा हुआ दिखाई देता है। बारिश की पहली फुहार पड़ते ही सड़कें आईना नहीं, गड्ढों का चेहरा दिखाने लगती हैं। सवाल यह नहीं कि सड़क पर गड्ढा है या नहीं, सवाल यह है कि आखिर इन गड्ढों में हर साल जनता का भरोसा क्यों दफन हो जाता है?" देश की राजधानी दिल्ली विकास, आधुनिकता और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों के लिए जानी जाती है। चौड़ी सड़कें, मेट्रो का विशाल नेटवर्क, फ्लाईओवर और नई-नई परियोजनाएँ इसकी पहचान हैं। लेकिन जैसे ही मानसून दस्तक देता है, विकास के ये दावे पानी में बहते नजर आने लगते हैं। सड़कें टूट जाती हैं, जलभराव हो जाता है और गहरे गड्ढे आम नागरिक के लिए जानलेवा खतरे में बदल जाते हैं। हर वर्ष करोड़ों रुपये सड़क निर्माण और मरम्मत पर खर्च किए जाते हैं। नालों की सफाई, जल निकासी और मानसून की तैयारियों के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन पहली तेज बारिश के बाद ही इन दावों की परतें उसी तरह उखड़ जाती हैं, जैसे सड़क का डामर। यह केवल इंजीनियरिंग की विफलता नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी तय करना सबसे कठिन काम बन जाता है। कहीं सड़क किसी विभाग के अधीन है, कहीं किसी दूसरी एजेंसी के। नागरिक शिकायत लेकर भटकता रहता है, लेकिन विभाग एक-दूसरे की ओर उंगली उठाते रहते हैं। इस बीच घायल व्यक्ति अस्पताल पहुँच जाता है और कभी-कभी कोई परिवार अपने प्रियजन को हमेशा के लिए खो देता है। दिल्ली में दोपहिया वाहन चालकों, साइकिल सवारों, ऑटो चालकों और पैदल यात्रियों के लिए ये गड्ढे किसी छिपे हुए खतरे से कम नहीं हैं। रात के समय या बारिश के दौरान पानी से भरे गड्ढे दिखाई भी नहीं देते। एक पल की चूक किसी की जिंदगी बदल सकती है। क्या राजधानी के नागरिकों को सुरक्षित सड़कें मिलना केवल चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? राजनीतिक दल सत्ता में हों या विपक्ष में, गड्ढों पर बयान देने में कभी पीछे नहीं रहते। विपक्ष में रहते हुए सड़कें मुद्दा बनती हैं और सत्ता में आने के बाद वही सड़कें फाइलों और बैठकों में खो जाती हैं। जनता को आरोप-प्रत्यारोप नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी सड़कें चाहिए जिन पर वह बिना डर के चल सके। अब समय आ गया है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी हो। जिस ठेकेदार का निर्माण कार्य कुछ महीनों में ही खराब हो जाए, उसे केवल नोटिस नहीं, बल्कि आर्थिक दंड और भविष्य की परियोजनाओं से वंचित करने जैसी कार्रवाई भी हो। हर सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी सार्वजनिक हो, ताकि नागरिकों को यह पता हो कि शिकायत किससे करनी है और जवाब कौन देगा। तकनीक के इस दौर में गड्ढों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और समयबद्ध मरम्मत की पारदर्शी व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। यदि राजधानी की सड़कें ही लोगों के लिए खतरा बन जाएँ, तो विकास के बड़े-बड़े दावे खोखले लगने लगते हैं। सड़कें केवल कंक्रीट और डामर का ढांचा नहीं होतीं, वे सरकार की प्राथमिकताओं और प्रशासन की संवेदनशीलता का आईना होती हैं। आखिरकार, प्रश्न केवल गड्ढों का नहीं है। प्रश्न उस व्यवस्था का है जो हर वर्ष वही गलती दोहराती है, वही वादे करती है और फिर उन्हीं गड्ढों में जनता का विश्वास गिरने देती है। अब फैसला जिम्मेदारों को करना है—क्या वे दिल्ली को गड्ढों से बाहर निकालेंगे, या आने वाली हर बारिश के साथ जनता फिर यही पूछेगी—"दिल्ली में गड्ढा है या गड्ढे में दिल्ली?"

रजनीकान्त तिवारी

नक्सलवाद के बाद घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार, अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंका

नीरज कुमार दुबे

देश को नक्सल आतंक की जकड़ से बाहर निकालने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंक दिया है। इस बार निशाने पर केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि घुसपैठ के जरिये सीमावर्ती इलाकों में बदलता जनसंख्या संतुलन, तस्करी, मादक पदार्थों का जाल, कट्टरपंथ, ड्रोन खतरे, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित छद्म युद्ध की पूरी रणनीति है। अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और सीमाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच देने का व्यापक अभियान अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अमित शाह का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ऐसे में यह अभियान वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के भारत की सुरक्षा का भी मजबूत आधार बनेगा। खुफियाऔर आतंकवाद प्रतिरोध हम आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए सरकार की नई और व्यापक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब केवल भूमि सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी इसी प्रकार का समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सम्मेलन में सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों, उनके समाधान और भविष्य की नीति तैयार करने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था अब केवल चौकियों और गश्त तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार सीमा सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों को साथ जोड़कर चार स्तरीय सुरक्षा तंत्र तैयार कर रही है। यही चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भविष्य में भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने का सबसे मजबूत आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। शहरऔर स्थानीय मार्गदर्शिका गृह मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की लगभग पंद्रह हजार किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इतनी विशाल सीमा की सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय समाज की भागीदारी, प्रशासनिक समन्वय और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग अनिवार्य है। इसी सोच के तहत सरकार अलग थलग सीमा चौकियों की पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़कर एकीकृत सुरक्षा तंत्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सीमा की परिकल्पना आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा व्यवस्था का रूप लेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नक्सलवाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में हिंसा के खिलाफ उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब अगले तीन वर्षों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी निर्णायक प्रहार किया जाएगा। साथ ही ऐसा मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे देश पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बने और भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ की संभावना लगभग समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले समस्याएं स्थायी होती थीं और समाधान अस्थायी, लेकिन अब सरकार समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर स्थायी समाधान तैयार कर रही है। देखा जाये तो इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलते जनसंख्या स्वरूप पर मोदी सरकार का विशेष ध्यान है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठ है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या अध्ययन अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत जनसंख्या में हो रहे अस्वाभाविक बदलावों का अध्ययन किया जाएगा, उनके कारणों की पहचान होगी और भविष्य में ऐसे परिवर्तनों को रोकने के उपाय सुझाए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्वाभाविक कारणों से होने वाली जनसंख्या वृद्धि पर कठोरता के साथ नियंत्रण किया जाएगा। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना सबसे निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक तत्काल पहुंचनी चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सरकार सरकार सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए आधारभूत ढांचे पर भी अभूतपूर्व निवेश कर रही है। अमित शाह ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना पर निवेश में चार सौ प्रतिशत की वृद्धि की गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सड़कों, संचार व्यवस्था, निगरानी तंत्र तथा अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत म्यांमार सीमा के सोलह सौ दस किलोमीटर लंबे हिस्से पर 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य केवल घुसपैठ रोकना नहीं, बल्कि छद्म युद्ध, अवैध हथियारों की आवाजाही, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित अन्य गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। साथ ही मोदी सरकार की सीमा सुरक्षा नीति केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम गांव को पहला गांव बताया है। इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार का मानना है कि जब सीमा पर बसे गांव समृद्ध होंगे, वहां के लोग सुरक्षित और आत्मनिर्भर होंगे, तभी सीमा सुरक्षा भी स्थायी रूप से मजबूत होगी। सामरिक दृष्टि से देखें तो यह नई नीति भारत की सुरक्षा सोच में बड़ा परिवर्तन है। अब देश केवल किसी घटना के बाद प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं रहेगा, बल्कि संभावित खतरों को पहले ही पहचानकर उन्हें रोकने की सक्रिय रणनीति अपनाई जाएगी। घुसपैठ, छद्म युद्ध, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रोन के जरिये हथियार पहुंचाना, साइबर अपराध और संगठित अपराध आज एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। ऐसे में इन सभी के खिलाफ एकीकृत सुरक्षा तंत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण, जनसंख्या संतुलन की निगरानी, आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती गांवों का विकास एक साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बना सकेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बाहरी चुनौती का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने की स्थिति में भी होगा।

बेटे के नजरिए से चुनती हूं फिल्म

मां बनने के बाद काम में बदलाव पर की बात

दिवाली पर नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' रिलीज होगी। काम में व्यस्त रहने के बावजूद काजल कहती हैं कि अब वह बहुत सोच-समझकर फिल्में चुनती हैं, खासकर मां बनने के बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई है।

मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा मुझ पर गर्व करे

एक इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने घर और काम को लेकर बात करते हुए कहा, 'शादी और बच्चे के बाद जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अब जब मैं कोई प्रोजेक्ट चुनती हूं, तो अपने बच्चे के नजरिए से सोचती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा मुझ पर गर्व करे। वह मेरी फिल्म देखे और कहे कि यह मेरी मां का काम है और यह बहुत अच्छा है। इसलिए अब मैं ज्यादा जिम्मेदारी और समझदारी के साथ फैसले लेती हूं।'

बेटा रामायण का बहुत बड़ा फैन

इसी वजह से 'रामायण' को लेकर उनकी एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा है। फिल्म को लेकर उन्होंने कहा, 'मेरा बेटा रामायण का बहुत बड़ा फैन है। वह रोज घर पर रामलीला करता है और किरदार निभाता है। जब मैंने उसे बताया कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं, तो वह बहुत खुश हो गया। मजेदार बात यह है कि उसका फेवरेट किरदार रावण है और मैं फिल्म में उसकी पत्नी मंदोदरी का रोल निभा रही हूं। जब 'रामायण' का पार्ट 2 आएगा, तब वह लगभग 5 साल का होगा और मैंने उससे कहा है कि वह अपनी पहली फिल्म थिएटर में देखेगा।'

दो हिस्सों में रिलीज होगी

'रामायण' नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' दो हिस्सों में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा।

प्रियदर्शन नहीं होंगे हेरा फेरी 3 का हिस्सा

प्रियदर्शन ने हाल ही में फिल्म 'भूत बंगला' का निर्देशन किया है। इन दिनों वह 'हैवान' पर काम कर रहे हैं। इस बीच निर्माता फिरोज ए नाडियाडवाला ने बताया है कि 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्टर नहीं करेंगे। उन्होंने अक्षय कुमार और परेश रावल जैसे एक्टर्स के साथ अपने रिश्तों के बारे में भी बात की। से बातचीत में फिरोज ने अक्षय कुमार के साथ अपने रिश्ते के बारे में कहा 'हमारा रिश्ता भाईचारे जैसा है। यह पैसे और दबाव से कहीं ऊपर है। हमारा रिश्ता 1996-97 से है। यह साथ रहने और साथ काम करने पर आधारित है और यही हमारा रिश्ता है।' परेश रावल की तारीफ करते हुए फिरोज ए नाडियाडवाला ने कहा 'डिक्शनरी में परेश भाई के बारे में बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। वह कमाल के हैं। उनके विचार, सपोर्ट और कोशिशें आम लोगों से कहीं बढ़कर हैं। उनके काम करने के तरीके में कुछ आध्यात्मिक बात है।'

जब 'हेरा फेरी 3' की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा गया, तो फिरोज ने संक्षेप में लेकिन भरोसा दिलाते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'सब कुछ सही रास्ते पर है और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।' जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रियदर्शन इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए वापस आएंगे, तो फिरोज ने सीधा और साफ जवाब दिया, जिससे अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं बची। उन्होंने कहा, 'नहीं, प्रियदर्शन इसका हिस्सा नहीं हैं।'

अपने हिंदी डेब्यू को तैयार

एक्टर अदिवि शेष

एक्टर-राइटर अदिवि शेष अब अपने हिंदी फिल्मी डेब्यू के लिए तैयार हैं। यह उनके करियर का अगला पड़ाव है, क्योंकि उन्हें तेलुगु सिनेमा के अलावा भी दर्शकों का प्यार लगातार मिल रहा है। उम्मीद है कि इस फिल्म की शूटिंग अक्तूबर में शुरू हो जाएगी। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'अदिवि शेष ने अच्छे कंटेंट वाली फिल्मों के जरिए दर्शकों के साथ मजबूत जुड़ाव बनाया है। 'मेजर' और 'डकैत' जैसी फिल्मों को मिले अच्छे रिस्पॉन्स से उनके दर्शकों का दायरा काफी बढ़ा है। अलग-अलग इंडस्ट्रीज और भाषाओं में उनके साथ काम करने को लेकर दिलचस्पी भी साफ तौर पर बढ़ रही है।'

महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल जगह है बॉलीवुड

अभिनेत्री कृति सेनन अपनी नई फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने अपने साथ हुए भेदभाव के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री को अक्सर उनके साथी अभिनेताओं से अलग तरह से जज किया जाता है। कृति ने इंडस्ट्री में काम करने की चुनौतियों के बारे में भी बात की है। बातचीत में कृति ने बताया कि उन्होंने मॉडलिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। वह जिन भी फील्ड्स का हिस्सा रही हैं, उनमें से बॉलीवुड ही वह जगह है जहां उन्हें सबसे ज्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ा है। उन्होंने याद किया कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, तो महिलाओं के लिए आज की तुलना में बहुत कम मौके थे।

लिंग के आधार पर है भेदभाव

कृति के मुताबिक, उस समय कई फिल्में मेल हीरो के आस-पास होती थीं, जिनमें अभिनेत्रियों को अक्सर सिर्फ रोमांटिक इंटरेस्ट के तौर पर लिया जाता था। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री धीरे-धीरे बड़ी हुई है, अब महिलाओं के लिए बेहतर लिखे गए रोल बन रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लिंग के आधार पर भेदभाव अभी भी कई तरह से मौजूद है। कृति ने फिल्म सेट पर मेल और फीमेल एक्टर्स पर लागू होने वाले अलग-अलग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वह अपने कैरेक्टर और सीन के बारे में सवाल पूछने के लिए जानी जाती हैं। मगर जब कोई महिला ऐसा करती है, तो उसे अक्सर मुश्किल या बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाली समझा जाता है।

कृति सेनन की हालिया रिलीज

कृति सेनन हाल ही में 'कॉकटेल 2' में नजर आई हैं। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में थे। फिल्म को आलोचकों से मिले-जुले रिव्यू मिले। कृति ने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है।

भारत-आस्ट्रेलिया ने रक्षा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारी को नये आयाम दिये: मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और आस्ट्रेलिया की साझेदारी साझे भविष्य को आकार देने वाली है और इस दिशा में आगे बढते हुए दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा , साइबर , परमाणु ऊर्जा , महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढाने के समझौते किये हैं। आस्ट्रेलिया की यात्रा पर गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को मेलबर्न में अपने आस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त घोषणा जारी की है।दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी तेजी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र दोनों देशों की साझा आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने

आतंकवाद से मिलकर लड़ने के संकल्प को दोहराया है और कहा है कि दुनिया भर में चल रहे टकरावों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को दो जीवंत लोकतांत्रिक और महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारी व्यापक सामरिक साझेदारी ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज की वार्ता के माध्यम से हमारे सहयोग में अनेक नए आयाम जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर शीघ्रता से कार्य करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए संतुलित, महत्त्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा। हम द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्योगों के बीच सहयोग पर विशेष बल दे रहे हैं। उन्होंने कहा ," प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को सहयोग प्रदान करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में 'छत पर सौर ऊर्जा प्रशिक्षण अकादमी' की स्थापना की है। यह अकादमी अनेक महिलाओं और युवाओं के कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देगी।" मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े हमारे उद्देश्यों को नई शक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि महत्त्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग हमारी सामरिक सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए अत्यंत आवश्यक है।" इसी सोच के साथ आज हमने साइबर सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी (एआई-पैक्ट्स) की शुरूआत की है। हम मिलकर महत्त्वपूर्ण खनिज गलियारे के निर्माण पर भी कार्य करेंगे।"

हिंद-प्रशांत क्षेत्र को भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों की साझा आकांक्षाओं का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा , "हमारा समुद्री सुरक्षा सहयोग मार्गदर्शिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे साझा प्रयासों को नई शक्ति प्रदान करेगी। हम जहाज निर्माण, जहाजों की मरम्मत तथा उनके रखरखाव के क्षेत्र में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे।" प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त घोषणा की है।

जीपीए के जरिए स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर दिल्ली सरकार सख्त, सब रजिस्ट्रारों को दस्तावेजों की गहन जांच के निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के माध्यम से संपत्तियों के हस्तांतरण में कथित रूप से हो रही स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर सख्त रुख अपनाते हुए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी सब-रजिस्ट्रारों को जीपीए से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच करने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, सरकार का उद्देश्य अचल संपत्तियों के पंजीकरण में होने वाले राजस्व नुकसान को रोकना, लैंड माफिया और फजीर्वाड़े पर अंकुश लगाना और सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए जीपीए के जरिए तैयार किए गए सभी संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की गहन जांच अनिवार्य कर दी गई है। रेखा गुप्ता ने कहा कि कई मामलों में संपत्ति की वास्तविक बिक्री और

मालिकाना हक के हस्तांतरण को सामान्य जीपीए का स्वरूप देकर केवल नाममात्र की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाता है। ऐसे दस्तावेजों में संपत्ति का कब्जा सौंपने, बिक्री करने या स्थायी अधिकार देने जैसी शर्तें शामिल होती हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टाम्प ड्यूटी की चोरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जीपीए दस्तावेज की जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि उसमें धन के लेनदेन का उल्लेख है या नहीं, क्या संपत्ति का कब्जा सौंपा जा रहा है, क्या दस्तावेज अपरिवर्तनीय है अथवा उसमें संपत्ति को बेचने, उपहार में देने, स्थानांतरित करने या गिरवी रखने का स्थायी अधिकार दिया गया है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि माता-पिता, जीवनसाथी, पुत्र, पुत्री, भाई और बहन जैसे रक्त संबंधों से बाहर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बनाई गई जीपीए को सब-रजिस्ट्रार सीधे पंजीकृत नहीं करेंगे। ऐसे सभी मामलों को अनिवार्य रूप से संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के पास भेजा जाएगा, जहां दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर उचित स्टाम्प ड्यूटी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स को ऐसे प्रत्येक मामले में 30 दिनों के भीतर लिखित और कारणयुक्त आदेश जारी करना होगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को अधिकतम तीन महीने तक बढ़ाया जा सकेगा।

सुखेंदु समेत 3 पूर्व टीएमसी सांसद बीजेपी में शामिल, ममता बनर्जी को तगड़ा झटका

नई दिल्ली। बीजेपी में शामिल होने वाले इन तीन प्रमुख नेताओं में सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक के नाम शामिल हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं के बीजेपी जॉइन करने की आधिकारिक घोषणा की है. बीजेपी नेता शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि तीनों नेताओं ने आज ही आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ली है. बता दें कि इन नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने से पहले राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया था. शमिक भट्टाचार्य ने सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक को बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. इस दौरान शमिक ने कहा, '34 साल तक लेफ्ट फ्रंट का राज था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का. पश्चिम बंगाल में इतने लंबे समय तक चली पॉलिटिक्स ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती दी और उसे नकार दिया, सेंटर के साथ सहयोग करने के बजाय, टकराव का रास्ता अपनाया गया, जिससे सारा डेवलपमेंट रुक गया।

दो तिहाई बहुमत की ओर बढ़ रहा एनडीए, विरोधियों में फूट से बढ़ी राज्यसभा में ताकत

नई दिल्ली। विरोधी दलों में टूट और बिखराव के साथ ही भाजपा की ताकत सदन में बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय में ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम चले हैं, जिन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की संसद के उच्च सदन में भी ताकत को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट के बाद उसके सात सांसद भाजपा में शामिल हुए और अब तृणमूल कांग्रेस से त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल हुए सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को भी पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्य सभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। उनकी जीत तय है, जिसके बाद ऐतिहासिक रूप से राजग सदन में दो तिहाई बहुमत की ओर तेजी से बढ़ता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्य सभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और

प्रकाश चिक बराइक ने पिछले दिनों पार्टी की सदस्यता सहित सदन की सदस्यता से भी त्याग-पत्र दिया। उसके बाद ही यह तीन सीटें रिक्त हो गईं। जैसी कि अटकलें लगाई जा रही थीं, तीनों ने ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और तुरंत ही भाजपा ने उन्हें राज्य सभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भी बना दिया। हाल ही में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त करने वाले भगवा दल के तीनों प्रत्याशियों का जीतना तय है। चुनाव 24 जुलाई को होना है। इसके बाद राज्य सभा में सत्ताधारी दल का गणित और मजबूत होने जा रहा है। दरअसल, 245 सदस्यों वाले उच्च सदन में अभी भाजपा के 114 सदस्य हैं जिसमें बंगाल के इन तीन सदस्यों के जुड़ने के बाद भाजपा 117 हो जाएगी। क्या कहते हैं आंकड़ें? अब यदि राजग की बात करें तो सहयागी दलों के 26 सदस्य हैं। इनमें यदि हाल ही में झारखंड से जीतकर आए तीन भाजपा समर्थित निर्दलीय सदस्यों को जोड़ लें तो राजग का कुनबा 146 सदस्यों का हो जाता है।चूंकि नामित सदस्य भी अधिकृत रूप से किसी खेमे में न शामिल हों, लेकिन परोक्ष रूप से इन्हें सत्ता पक्ष का समर्थक ही माना जाता है। ऐसे में यदि जब सदन में नंबर गेम की जरूरत होगी तो सात नामित सदस्यों को इनमें शामिल करते ही संख्या 153 हो जाएगी। वहीं, दो तिहाई बहुमत के लिए 164 का आंकड़ा चाहिए, जिससे राजग सिर्फ 13 अंकों से दूर रह जाएगा। इस बीच चर्चा है कि टीएमसी के शेष रह गए दस राज्य सभा सदस्यों में से तीन या चार के भी तृणमूल से छिटकने की संभावना है। ऐसा हुआ तो भाजपा को दो तिहाई बहुमत पाने के लिए लगभग सात-आठ सांसदों की ही आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि एनडीए को इस आंकड़े तक पहुंचाने में आम आदमी पार्टी की टूट की बड़ी भूमिका है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक रजनीकान्त तिवारी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स ए-9 सराय पीपल थला एक्सटेंशन दिल्ली-110033 से छपवाकर कार्यालय असर न्यूज सी-21, नेताजी रोड, आदर्श नगर दिल्ली-110033 से प्रकाशित किया। किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा दिल्ली की अदालत में होगा तथा किसी भी प्रकाशित लेखन सामग्री से प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। R.N.I. No. DELHIN/68203/98